SWACHH BHARAT MISSION (SBM) Urban 2.0: एसबीएम अर्बन 2.0:

- As a goal of the SBM Urban 2.0, which was launched in 2021, all legacy landfills in the country are to be cleared by 2025-2026.
  एसबीएम अर्बन 2.0 के लक्ष्य के रूप में, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, देश में सभी पुराने लैंडफिल को 2025–2026 तक साफ किया जाना है।
- Ahmedabad: Cleared 4.3 acres of land from 2.30 lakh tonnes of waste at Bopal Ghuma site. Redeveloped into an ecological park costing Rs. 8 crore. Work ongoing at larger Pirana landfill (84 acres) with 54% cleared.
  अहमदाबाद: बोपल घुमा स्थल पर 2.30 लाख टन कचरे से 4.3 एकड़ भूमि साफ की गई। की लागत से एक पारिस्थितिक पार्क के रूप में पुनर्विकसित किया गया। 8 करोड़. 54: मंजूरी के साथ बड़े पिराना लैंडफिल (84 एकड़) पर काम जारी है।

- Nagpur: Remediated 35 acres of landfill containing 10 lakh metric tonnes of waste. Site planned for an integrated waste management project.
  नागपुर: 10 लाख मीट्रिक टन कचरे वाले 35 एकड़ लैंडफिल का समाधान किया गया। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए साइट की योजना बनाई गई।
- Pune: Cleared 75 acres of land at Vanaz landfill, remediating 37 lakh tonnes of waste. The site is now the Hill View Park Car Depot, part of the Pune Metro Rail project.
  पुणे: वनाज लैंडफिल में 75 एकड़ भूमि साफ की गई, जिससे 37 लाख टन कचरे का समाधान हुआ। यह साइट अब हिल व्यू पार्क कार डिपो है, जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना का हिस्सा है।
- These efforts are part of the SBM Urban 2.0 goal to clear all legacy landfills by 2025-2026.
  ये प्रयास 2025–2026 तक सभी पुराने लैंडफिल को साफ करने के एसबीएम अर्बन 2.0 लक्ष्य का हिस्सा हैं।

Jal Hi AMRIT Programme: जल ही अमृत कार्यक्रम:

- The Union Minister for Housing and Urban Affairs said that the government has introduced the Jal Hi AMRIT scheme in its first 100 days. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में जल ही अमृत योजना शुरू की है।
- Jal Hi AMRIT Programme was launched under the AMRUT 2.0 scheme. जल ही अमृत कार्यक्रम अमृत 2.0 योजना के तहत शुरू किया गया था।
- Under this initiative, it is envisaged to incentivise State & UTs to manage the used water (sewage) treatment plants (UWTPs/ STPs) efficiently to ensure recyclable good quality treated water, meeting environmental standards, on a sustained basis. इस पहल के तहत, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को उपयोग किए गए जल (सीवेज) उपचार संयंत्रों (यूडब्ल्यूटीपीध्एसटीपी) को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है ताकि पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते हुए, निरंतर आधार पर पुनर्चक्रण योग्य अच्छी गुणवत्ता वाले उपचारित पानी को सुनिश्चित किया जा सके।

Jal Hi AMRIT Programme: जल ही अमृत कार्यक्रमः

- The main focus is thus on capacity building & incentivizing qualitative improvements in the treated discharge effluent.
  इस प्रकार मुख्य ध्यान क्षमता निर्माण और उपचारित प्रवाहित प्रवाह में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करने पर है।
- A mid-course assessment and water quality testing will be conducted, culminating in a final assessment & award of Clean Water Credits in terms of a Star-rating (between 3 stars to 5 stars) certificate valid for six months.
  एक मध्य–पाठ्यक्रम मूल्यांकन और जल गुणवत्ता परीक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप छह महीने के लिए वैध स्टार–रेटिंग (3 स्टार से 5 स्टार के बीच) प्रमाणपत्र के संदर्भ में स्वच्छ जल क्रेडिट का अंतिम मूल्यांकन और पुरस्कार दिया जाएगा।

AMRUT 2.0 scheme: अमृत 2.0 योजनाः

- It was launched for a period of five years, from the financial year 2021-22 to the financial year 2025-26. इसे वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक पांच साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था।
- It is designed to provide universal coverage of water supply through functional taps to all households in all the statutory towns in the country and coverage of sewerage/septage management in 500 cities covered in the first phase of the AMRUT scheme.
  इसे देश के सभी वैधानिक कस्बों में सभी घरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेजध्सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan : Jharkhand
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानः झारखंड

- Prime Minister of India recently launched the Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan in Jharkhand with an outlay of around Rs 80,000 crore.
  भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में लगभग 80,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया।
- Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan aims to foster holistic development in tribal villages, bringing transformative changes to the socio-economic landscape of the region.
  धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य आदिवासी गांवों में समग्र विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव लाना है।

Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan : Jharkhand

- The Abhiyan will cover around 63,843 villages, benefiting more than 5 crore tribal people in 549 districts, and 2,911 blocks spread across all tribal majority villages and aspirational blocks in 30 States/UTs. यह अभियान लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा, जिससे 549 जिलों के 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होगा, और 30 राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुसंख्यक गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 2,911 ब्लॉकों को लाभ मिलेगा।
- It envisions saturation of critical gaps in ***social infrastructure, health, education, and livelihood*** through 25 interventions implemented by 17-line ministries of Govt of India by convergence and outreach; and ensures holistic and sustainable development of tribal areas and communities.यह भारत सरकार के 17–लाइन मंत्रालयों द्वारा अभिसरण और आउटरीच द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल की संतृप्ति की कल्पना करता हैय और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करता है।

- The scheme has a total outlay of Rs.79,156 crores (Central Share: Rs.56,333 crore and State Share: Rs. 22,823 crore).
  इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्साः 56,333 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्साः 22,823 करोड़ रुपये) है।
- It has been planned based on the learning and success of Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN), which was launched in November 2023.
  इसकी योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की सीख और सफलता के आधार पर बनाई गई है, जिसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था।
- With a budget outlay of Rs. 24,104 crores, the PM-JANMAN focuses on the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) population.
  रुपये के बजट परिव्यय के साथ. 24,104 करोड़ रुपये का पीएम–जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) आबादी पर केंद्रित है।

PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप योजना:

- The Prime Minister's Internship Scheme, which was announced by the Union Finance Minister during her Budget speech was launched.
  प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना, जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान की थी, शुरू की गई थी।
- PM Internship Scheme will enhance youth employability in India by offering them hands-on exposure to real-world business environments.
  पीएम इंटर्नशिप योजना भारत में युवाओं को वास्तविक दुनिया के कारोबारी माहौल में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके रोजगार क्षमता बढ़ाएगी।
- The scheme represents a transformative opportunity to bridge the skills gap and drive sustainable growth in India.
  यह योजना कौशल अंतर को पाटने और भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर का प्रतिनिधित्व करती है।

PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप योजनाः

- The scheme aims to provide internship opportunities to one crore youth over five years, in the top 500 companies. इस योजना का लक्ष्य शीर्ष 500 कंपनियों में पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।
- The pilot project will be implemented through an online portal managed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). पायलट प्रोजेक्ट को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा प्रबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- A monthly stipend of ₹4,500 will be provided to the interns from the central government via DBT (Direct Benefit transfer), with an additional ₹500 offset provided by the company's Corporate Social Responsibility (CSR) केंद्र सरकार की ओर से प्रशिक्षुओं को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से ₹4,500 का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा, साथ ही कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) द्वारा अतिरिक्त ₹500 की छूट भी प्रदान की जाएगी।

PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप योजना:

- They will also be provided a one-time grant of Rs 6,000 upon joining and insurance coverage under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Suraksha Bima Yojana.
  उन्हें शामिल होने पर 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा।
- Internship period: One year
  इंटर्नशिप अवधि: एक वर्ष

Eco-mark Scheme : Revised इको–मार्क योजनाः संशोधित

- The Ecomark Scheme was introduced to promote eco-friendly products in alignment with the 'LiFE' (Lifestyle for Environment) mission initiated in 2021. इकोमार्क योजना 2021 में शुरू किए गए LIFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) मिशन के अनुरूप पर्यावरण–अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।
- The revised scheme, notified in 2024, replaces the earlier 1991 version, and focuses on reducing ***environmental impacts, promoting resource efficiency, and encouraging sustainable production and consumption***. 2024 में अधिसूचित संशोधित योजना, पहले के 1991 संस्करण की जगह लेती है, और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने और टिकाऊ उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
- Accreditation of products based on specific environmental criteria, ensuring minimal environmental harm. विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों के आधार पर उत्पादों का प्रमाणीकरण, न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति सुनिश्चित करना।

Eco-mark Scheme : Revised इको–मार्क योजना: संशोधित

- Reduction in energy consumption and promoting a circular economy by utilizing recycled materials and eco-friendly production methods.
  ऊर्जा की खपत में कमी और पुनर्नवीनीकरण सामग्री और पर्यावरण–अनुकूल उत्पादन विधियों का उपयोग करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- The scheme mandates accurate labelling to avoid misleading claims about product sustainability.
  उत्पाद स्थिरता के बारे में भ्रामक दावों से बचने के लिए योजना सटीक लेबलिंग को अनिवार्य बनाती है।

Eco-mark Scheme : Revised इको–मार्क योजना: संशोधित

- Implementation is overseen by the Central Pollution Control Board (CPCB) and Bureau of Indian Standards (BIS).
  कार्यान्वयन की देखरेख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा की जाती है।
- The scheme is a step towards achieving sustainability goals, supporting both consumer awareness and motivating manufacturers to adopt eco-friendly practices.
  यह योजना स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने, उपभोक्ता जागरूकता का समर्थन करने और निर्माताओं को पर्यावरण–अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक कदम है।

Indigenous Sex Sorted Semen And Unified Genomic Chip: Livestock Scheme
स्वदेशी लिंग क्रमबद्ध वीर्य और एकीकृत जीनोमिक चिपः पशुधन योजना

- The Prime Minister of India launched two programs of the Animal Husbandry Department for the benefit of the livestock – ‘ ***Indigenous Sex Sorted Semen***’ and ‘ ***Unified Genomic Chip***’.
  भारत के प्रधान मंत्री ने पशुधन के लाभ के लिए पशुपालन विभाग के दो कार्यक्रम शुरू किए – ‘स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड वीर्य’ और ‘यूनिफाइड जीनोमिक चिप‘।
- Unified Genomic Chip is aimed at helping farmers identify high-quality cattle early and enhance dairy farming efficiency in India.
  यूनिफाइड जीनोमिक चिप का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों की शीघ्र पहचान करने और भारत में डेयरी फार्मिंग दक्षता बढ़ाने में मदद करना है।

Indigenous Sex Sorted Semen And Unified Genomic Chip: Livestock Scheme

- The chip comes in two versions चिप दो संस्करणों में आती है
- The '***Gau Chip***' for cattle and the '***Mahish Chip***' for buffalo.
  मवेशियों के लिए 'गौ चिप' और भैंस के लिए 'महिष चिप'।
- It is developed by the Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD), under the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.
  इसे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) द्वारा विकसित किया गया है।
- The purpose of this chip is to help farmers make informed decisions on animal selection by identifying young, high-quality bulls at an early age.
  इस चिप का उद्देश्य किसानों को कम उम्र में युवा, उच्च गुणवत्ता वाले बैलों की पहचान करके पशु चयन पर सूचित निर्णय लेने में मदद करना है।

Indigenous Sex Sorted Semen And Unified Genomic Chip: Livestock Scheme

- The chip is tailored for Indian cattle breeds and will help improve the quality of cattle and enhance the dairy farming sector.
  चिप को भारतीय मवेशियों की नस्लों के लिए तैयार किया गया है और यह मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार करने और डेयरी फार्मिंग क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करेगा।
- Sex Sorted Semen is the 'gender selected' semen used by Artificial Insemination (AI) for cattle and buffaloes to produce more than 90% selected gender (females).
  सेक्स सॉर्टेड सीमेन 'लिंग चयनित' वीर्य है जिसका उपयोग कृत्रिम गर्भाधान (एआई) द्वारा मवेशियों और भैंसों के लिए 90: से अधिक चयनित लिंग (मादा) पैदा करने के लिए किया जाता है।

Indigenous Sex Sorted Semen And Unified Genomic Chip: Livestock Scheme

- It is very effective in breed improvement and till now it was manufactured by multinational companies. यह नस्ल सुधार में बहुत कारगर है और अब तक इसका निर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता था।
- The National Dairy Development Board under the Department of Animal Husbandry and Dairying, has developed the indigenous technology of sex-sorted semen worth Rs. 250. पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लिंग–आधारित वीर्य की स्वदेशी तकनीक विकसित की है।
- IVF technology (commonly known as test tube baby technology) is also being used for this purpose. इस उद्देश्य के लिए आईवीएफ तकनीक (जिसे आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के रूप में जाना जाता है) का भी उपयोग किया जा रहा है।
- It has now planned to produce a minimum of 10 lakh sexed semen doses annually for the ongoing artificial insemination (AI) programme.इसने अब चल रहे कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कार्यक्रम के लिए सालाना न्यूनतम 10 लाख लिंगयुक्त वीर्य खुराक का उत्पादन करने की योजना बनाई है।

Ni-kshay Poshan Yojana: नि–क्षय पोषण योजना:

- The Union Health Ministry has doubled the monthly nutrition support under Ni-Kshay Poshan Yojana from the existing Rs 500 to Rs 1,000 per month for all TB patients, during treatment. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपचार के दौरान सभी टीबी रोगियों के लिए नि–क्षय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण सहायता मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी है।
- Ni-kshay Poshan Yojana (NPY) launched by the Ministry of Health and Family Welfare (MoH&FW) as a centrally sponsored scheme under the National Health Mission (NHM) in April 2018. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (डवभ–ॅ) द्वारा अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छभ्ड) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नि–क्षय पोषण योजना (छच्ल) शुरू की गई।
- It is a direct benefit transfer (DBT) scheme under the National Tuberculosis Elimination Program (NTEP) in India. यह भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना है।

Ni-kshay Poshan Yojana: नि–क्षय पोषण योजनाः

- Objective is to provide incentives for nutritional support to tuberculosis (TB) patients. इसका उद्देश्य तपेदिक (टीबी) रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- All notified TB patients are beneficiaries of the scheme.
  सभी अधिसूचित टीबी रोगी योजना के लाभार्थी हैं।
- All patients with TB who are notified to the government on or after April 1, 2018, including those who are already being treated for TB, are eligible for financial incentives.1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद सरकार को सूचित किए गए टीबी के सभी मरीज, जिनमें पहले से ही टीबी का इलाज चल रहा है, वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

Ni-kshay Poshan Yojana: नि–क्षय पोषण योजनाः

- To be eligible for the incentives, patients must be registered or notified on the NIKSHAY portal.
  प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए, रोगियों को निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत या सूचित किया जाना चाहिए।
- Financial incentive of 1000/- per month for each notified TB patient for the duration for which the patient is on anti-TB treatment.
  प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी को उस अवधि के लिए 1000ध्– प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन, जिस अवधि के लिए रोगी एंटी–टीबी उपचार पर है।

Ni-kshay Poshan Yojana: नि–क्षय पोषण योजनाः

- The incentives can be distributed in Cash (only via DBT, preferably through Aadhaar-enabled bank accounts) or in-kind.
  प्रोत्साहन नकद (केवल डीबीटी के माध्यम से, अधिमानतः आधार–सक्षम बैंक खातों के माध्यम से) या वस्तु के रूप में वितरित किया जा सकता है।
- This scheme is implemented across all States and UTs in India.
  यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की गई है।

World Association Of Zoos And Aquariums: चिड़ियाघरों और एक्वैरियम का विश्व संघः

- The World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) recently suspended the membership of the Delhi Zoo over concerns about the treatment of its alone African elephant named ***Shankar***. वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम (WAZA) ने हाल ही में शंकर नाम के एकमात्र अफ्रीकी हाथी के इलाज के बारे में चिंताओं पर दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता निलंबित कर दी है।
- World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) is the umbrella organization for the World Zoo and Aquarium community. वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम (।।) विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम समुदाय के लिए एक प्रमुख संगठन है।
- Established in 1935, it is the only organisation representing zoos and aquariums at the global level.1935 में स्थापित, यह वैश्विक स्तर पर चिड़ियाघरों और एक्वैरियम का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र संगठन है।

World Association Of Zoos And Aquariums: चिड़ियाघरों और एक्वैरियम का विश्व संघः

- WAZA's mission is to guide, encourage, and support the zoos, aquariums, and like-minded organisations of the world in animal care and welfare, environmental education, and global conservation. WAZA का मिशन जानवरों की देखभाल और कल्याण, पर्यावरण शिक्षा और वैश्विक संरक्षण में दुनिया के चिड़ियाघरों, एक्वैरियम और समान विचारधारा वाले संगठनों का मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समर्थन करना है।
- Its members include leading zoos and aquariums, and regional and national Associations of Zoos and Aquariums, as well as some affiliate organizations, such as zoo veterinarians or zoo educators, from all around the world. इसके सदस्यों में अग्रणी चिड़ियाघर और एक्वेरियम, और चिड़ियाघर और एक्वेरियम के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संघ, साथ ही दुनिया भर के चिड़ियाघर के पशुचिकित्सक या चिड़ियाघर शिक्षक जैसे कुछ संबद्ध संगठन शामिल हैं।

World Association Of Zoos And Aquariums: चिड़ियाघरों और एक्वैरियम का विश्व संघः

Activities of WAZA are: WAZA की गतिविधियाँ हैं:

- Promoting cooperation between zoological gardens and aquariums in relation to the conservation, management, and breeding of animals in captivity. कैद में जानवरों के संरक्षण, प्रबंधन और प्रजनन के संबंध में प्राणी उद्यान और एक्वैरियम के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- Encouraging highest standards of animal welfare and husbandry. पशु कल्याण और पालन के उच्चतम मानकों को प्रोत्साहित करना।

World Association Of Zoos And Aquariums: चिड़ियाघरों और एक्वैरियम का विश्व संघः

- Promoting and coordinating cooperation between national and regional associations and their constituents. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संघों और उनके घटकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और समन्वय करना।
- Assist in representing zoological gardens and aquariums in other international organizations or assemblies. अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या सभाओं में प्राणी उद्यानों और एक्वैरियमों का प्रतिनिधित्व करने में सहायता करना।
- Promoting wildlife conservation, environmental research, and environmental education. वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना।

World Association Of Zoos And Aquariums: चिड़ियाघरों और एक्वैरियम का विश्व संघः

- WAZA has formed partnerships with leading international conservation organisations. WAZA ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संगठनों के साथ साझेदारी बनाई है।
- Together, they are committed to tackling global issues such as the illegal wildlife trade, coral-reef restoration, marine litter, sustainable palm oil and climate change. साथ में, वे अवैध वन्यजीव व्यापार, मूंगा–चट्टान बहाली, समुद्री कूड़े, स्थायी पाम तेल और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

CURRENT AFFAIRS

Nijut Moina Scheme Launched in Assam to Fight Child Marriage:

बाल विवाह से लड़ने के लिए असम में निजुत मोइना योजना शुरू की गई:

- Chief Minister Himanta Biswa Sarma of Assam has initiated the disbursement of monthly financial assistance under the Nijut Moina scheme. This step marks a decisive phase in the government's ongoing battle against this social issue, aiming to provide crucial support to families

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने निजुत मोइना योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता के वितरण की शुरुआत की है। यह कदम इस सामाजिक मुद्दे के खिलाफ सरकार की चल रही लड़ाई में एक निर्णायक चरण का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना है

Atal Pension Yojana Crosses 7 Crore Enrollments Milestone:

अटल पेंशन योजना ने 7 करोड़ नामांकन का मील का पत्थर पार किया:

- The Atal Pension Yojana (APY), launched in 2015 to provide a universal social security system for all, particularly the underprivileged and workers in the unorganized sector, has achieved a major milestone. As of FY 2024-25, total enrollments have surpassed 7 crore, with over 56 lakh new enrollments added in the current financial year.

  सभी, विशेषकर वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2024–25 तक, कुल नामांकन 7 करोड़ से अधिक हो गया है, चालू वित्त वर्ष में 56 लाख से अधिक नए नामांकन जुड़े हैं।

Humsafar Policy: हमसफर नीतिः

- Aimed at providing wayside amenities along national highways, the Union Road Transport Minister recently launched 'Humsafar Policy.
  राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने हाल ही में 'हमसफर नीति' लॉन्च की है।
- Humsafar Policy is a comprehensive initiative aimed at enhancing facilities along India's national highways.
  हमसफर नीति एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं बढ़ाना है।

Humsafar Policy: हमसफर नीतिः

- The policy seeks to improve the convenience, safety, and comfort of highway travellers by providing a wide range of services at key locations along the road network.
  यह नीति सड़क नेटवर्क के साथ प्रमुख स्थानों पर सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करके राजमार्ग यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम में सुधार करना चाहती है।
- Under this policy, rest stops equipped with essential amenities like clean washrooms, food courts, parking spaces, and first-aid services will be developed across major highways.
  इस नीति के तहत, प्रमुख राजमार्गों पर स्वच्छ शौचालय, फूड कोर्ट, पार्किंग स्थान और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित विश्राम स्थल विकसित किए जाएंगे।

Humsafar Policy: हमसफर नीतिः

- Dedicated rooms for baby care, equipped with changing tables and other essentials, will be provided for families travelling with young children.
  छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए शिशु देखभाल के लिए समर्पित कमरे, चेंजिंग टेबल और अन्य आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित, उपलब्ध कराए जाएंगे।
- It includes provisions for creating multi-utility spaces at regular intervals to cater to the diverse needs of travelers.
  इसमें यात्रियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित अंतराल पर बहु–उपयोगी स्थान बनाने के प्रावधान शामिल हैं।

Humsafar Policy: हमसफर नीतिः

- These spaces will feature fuel stations, Electric Vehicle (EV) charging points, convenience stores, and other roadside services that are expected to reduce driver fatigue and improve overall road safety.
  इन स्थानों में ईंधन स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट, सुविधा स्टोर और अन्य सड़क किनारे सेवाएं होंगी, जिनसे ड्राइवर की थकान कम होने और समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है।
- Dormitories will be introduced at fuel stations to provide short-term accommodation for truck drivers, travellers, and those requiring a rest break during long-distance travel.
  ट्रक ड्राइवरों, यात्रियों और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान आराम की आवश्यकता वाले लोगों के लिए अल्पकालिक आवास प्रदान करने के लिए ईंधन स्टेशनों पर शयनगृह शुरू किए जाएंगे।

Humsafar Policy: हमसफर नीतिः

- Accessibility will be a key focus, with wheelchair provisions made available for differently-abled travellers.
  दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर प्रावधान उपलब्ध कराने के साथ–साथ पहुंच पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा।
- The initiative also aims to promote sustainability by incorporating green technologies, such as solar-powered facilities and EV infrastructure, contributing to India's environmental goals.
  इस पहल का उद्देश्य भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान करते हुए, सौर ऊर्जा से संचालित सुविधाओं और ईवी बुनियादी ढांचे जैसी हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल करके स्थिरता को बढ़ावा देना है।

MAHA-EV Mission: महा–ईवी मिशनः

- The Anusandhan National Research Foundation announced the launch of the Mission for Advancement in High-Impact Areas -Electric Vehicle (MAHA- EV) Mission.
  अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन–इलेक्ट्रिक वाहन (एमएएचए–ईवी) मिशन के शुभारंभ की घोषणा की।
- MAHA-EV Mission focuses on the development of key EV technologies to reduce dependency on imports, promote domestic innovation, and position India as a global leader in the EV sector.
  MAHA&EV मिशन आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को म्ट क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख EV प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है।

MAHA-EV Mission: महा–ईवी मिशन:

- It is part of ANRF's Advancement in High-Impact Areas (MAHA) program designed to catalyze multi-institutional, multi-disciplinary, and multi-investigator collaboration to tackle critical scientific challenges.
  यह एएनआरएफ के एडवांसमेंट इन हाई–इम्पैक्ट एरियाज (एमएएचए) कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए बहु–संस्थागत, बहु–अनुशासनात्मक और बहु–अन्वेषक सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- It aims to accelerate technological advancement in key sectors that have a high impact on the nation's future growth to create a global standing in the area.
  इसका उद्देश्य उन प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति में तेजी लाना है जो क्षेत्र में वैश्विक स्थिति बनाने के लिए देश के भविष्य के विकास पर उच्च प्रभाव डालते हैं।

MAHA-EV Mission: महा–ईवी मिशनः

- It is concentrating on three critical technology verticals– Tropical EV Batteries and Battery Cells, Power Electronics, Machines, and Drives (PEMD) and Electric Vehicle Charging Infrastructure.
  यह तीन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों– ट्रॉपिकल ईवी बैटरी और बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और ड्राइव (पीईएमडी) और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- The mission will enhance domestic capabilities in the design and development of essential EV components.
  यह मिशन आवश्यक ईवी घटकों के डिजाइन और विकास में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाएगा।

MAHA-EV Mission: महा–ईवी मिशनः

- It will strengthen competitiveness and position India as a hub for EV component development, driving global competitiveness and innovation.
  यह प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा और भारत को ईवी घटक विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- By accelerating the shift towards electric mobility, it will contribute to a greener and sustainable future.
  इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव में तेजी लाकर, यह एक हरित और टिकाऊ भविष्य में योगदान देगा।

e-Migrate Portal: ई–माइग्रेट पोर्टल:

- The Union External Affairs Minister and Labour and Employment Minister launched the updated e-Migrate portal and mobile app.
  केंद्रीय विदेश मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री ने अद्यतन ई–माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
- e-Migrate Portal is an online platform launched by the Government of India to facilitate and manage the migration of Indian workers seeking employment abroad.
  ई–माइग्रेट पोर्टल विदेश में रोजगार चाहने वाले भारतीय श्रमिकों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने और प्रबंधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है।

e-Migrate Portal: ई–माइग्रेट पोर्टलः

- It aims to provide a safe and transparent framework for migrant workers by offering various services, including information access, documentation, helpline support, integration with services and awareness campaigns
  इसका उद्देश्य सूचना पहुंच, दस्तावेजीकरण, हेल्पलाइन समर्थन, सेवाओं के साथ एकीकरण और जागरूकता अभियान सहित विभिन्न सेवाओं की पेशकश करके प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी ढांचा प्रदान करना है।
- It promotes safe and legal mobility channels for Indian migrants.
  यह भारतीय प्रवासियों के लिए सुरक्षित और कानूनी गतिशीलता चौनलों को बढ़ावा देता है।

e-Migrate Portal: ई–माइग्रेट पोर्टलः

- The enhanced e-Migrate portal aligns with the United Nations' Sustainable Development Goal 10, promoting orderly and responsible migration.
  उन्नत ई–माइग्रेट पोर्टल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 10 के अनुरूप है, जो व्यवस्थित और जिम्मेदार प्रवासन को बढ़ावा देता है।
- The upgraded platform offers 24/7 multilingual helpline support and a feature for feedback, ensuring timely redressal of issues faced by workers abroad, especially in the Gulf region.
  उन्नत प्लेटफॉर्म 24ध्7 बहुभाषी हेल्पलाइन सहायता और फीडबैक के लिए एक सुविधा प्रदान करता है, जो विदेशों में, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं का समय पर निवारण सुनिश्चित करता है।

e-Migrate Portal: ई–माइग्रेट पोर्टल:

- The revamped system integrates with Digilocker, enabling secure, paperless document submission.
  संशोधित प्रणाली डिजिलॉकर के साथ एकीकृत होती है, जो सुरक्षित, कागज रहित दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है।
- Additionally, a partnership with Common Service Centres (CSCs) will expand immigration services to rural areas in local languages, enhancing accessibility.
  इसके अतिरिक्त, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ साझेदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में आव्रजन सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे पहुंच बढ़ेगी।

e-Migrate Portal: ई–माइग्रेट पोर्टलः

- The platform also supports job-seekers by offering a one-stop marketplace for overseas employment opportunities.
  यह मंच विदेशी रोजगार के अवसरों के लिए वन–स्टॉप मार्केटप्लेस की पेशकश करके नौकरी चाहने वालों का भी समर्थन करता है।

SAMARTH Scheme: Extended समर्थ योजनाः विस्तारित

- Central government has been extended the Samarth Scheme for two years (FY 2024-25 and 2025-26) with a budget of Rs. 495 Crore to train 3 lakh persons in textile-related skills.
  केंद्र सरकार ने रुपये के बजट के साथ समर्थ योजना को दो साल (वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26) के लिए बढ़ा दिया है। कपड़ा–संबंधित कौशल में 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपये।
- The Scheme for Capacity Building in Textiles Sector (SAMARTH) is a demand-drivenand placement-oriented umbrella skilling programme.
  कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) एक मांग–संचालित और प्लेसमेंट–उन्मुख अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है।

SAMARTH Scheme: Extended समर्थ योजनाः विस्तारित

- It aims to incentivize and supplementthe efforts of the industry in creating jobs in the organized textile and related sectors, covering the entire value chain of textiles, excluding Spinning and Weaving. इसका उद्देश्य कताई और बुनाई को छोड़कर, कपड़ा की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए, संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पूरक करना है।
- In addition to the entry-level skilling, a special provision for upskilling/ re-skilling programme has also been operationalized under the scheme towards improving the productivity of the existing workers in the Apparel & Garmenting segments. प्रवेश स्तर के कौशल के अलावा, परिधान और गारमेंटिंग क्षेत्रों में मौजूदा श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार की दिशा में योजना के तहत अपस्किलिंगध्री–स्किलिंग कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रावधान भी संचालित किया गया है।

SAMARTH Scheme: Extended समर्थ योजनाः विस्तारित

- Under this scheme skilling programme is implemented through the following Implementing Agencies: इस योजना के तहत कौशल कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता हैः
- Textile Industry. Institutions/Organizations of the Ministry of Textiles/State Governments having training infrastructure and placement tie-ups with the textile industry. कपड़ा उद्योग। कपड़ा मंत्रालयध्राज्य सरकारों के संस्थानध्संगठन जिनके पास कपड़ा उद्योग के साथ प्रशिक्षण अवसंरचना और प्लेसमेंट संबंध हैं।
- Reputed training institutions/ NGOs/ Societies/ Trusts/ Organizations/ Companies /Start-Ups / Entrepreneurs active in the textile sector having placement tie-ups with the textile industry. कपड़ा क्षेत्र में सक्रिय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानध्एनजीओध्सोसायटीध्ट्रस्टध्संगठनध्कंपनियांध्स्टार्ट–अपध्उद्यमी जिनका कपड़ा उद्योग के साथ प्लेसमेंट समझौता है।

Namo Bharat Diwas: नमो भारत दिवस:

- The first anniversary of Namo Bharat train operations was celebrated as Namo Bharat Diwas in New Delhi, marking a significant milestone in India's transportation history. नमो भारत ट्रेन संचालन की पहली वर्षगांठ को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस के रूप में मनाया गया, जो भारत के परिवहन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) organized the event, attended by Union Minister of Housing and Urban Affairs and Union Minister of State for Housing and Urban Affairs. During the celebration, excellence awards were presented to outstanding employees who contributed to the success of the Namo Bharat initiative.राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने भाग लिया। उत्सव के दौरान, नमो भारत पहल की सफलता में योगदान देने वाले उत्कृष्ट कर्मचारियों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए।

Mission Basundhara 3.0 : Assam मिशन बसुंधरा 3.0: असम

- Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma officially launched Mission Basundhara 3.0 at an event held at Srimanta Sankardev Kalakshetra in Guwahati. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर मिशन बसुंधरा 3.0 की शुरुआत की।
- This ambitious initiative is designed to empower indigenous communities by providing them with formal land rights, ensuring greater security and recognition of their holdings. The world's total public debt is projected to exceed $100 trillion for the first time in 2024. यह महत्वाकांक्षी पहल स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करके, उनकी जोत की अधिक सुरक्षा और मान्यता सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई है। दुनिया का कुल सार्वजनिक ऋण 2024 में पहली बार 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

Mission Basundhara 3.0 : Assam मिशन बसुंधरा 3.0: असम

- This figure is expected to reach 93% of global GDP by the end of 2024 and approach 100% by 2030, surpassing the 99% peak seen during the COVID-19 pandemic. यह आंकड़ा 2024 के अंत तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 93: तक पहुंचने और 2030 तक 100: तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि ब्वटप्क–19 महामारी के दौरान देखे गए 99: शिखर को पार कर जाएगा।

RCS-UDAN : New Airports आरसीएस–उड़ान: नए हवाई अड्डे

- The Prime Minister inaugurated three airports under the Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) in Rewa (Madhya Pradesh), Ambikapur (Chhattisgarh), and Saharanpur (Uttar Pradesh). प्रधान मंत्री ने रीवा (मध्य प्रदेश), अंबिकापुर (छत्तीसगढ़), और सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस–उड़ान) के तहत तीन हवाई अड्डों का उद्घाटन किया।
- These airports aim to enhance air travel accessibility and will soon commence flights, furthering the mission of improving infrastructure in underserved regions. इन हवाई अड्डों का लक्ष्य हवाई यात्रा की पहुंच बढ़ाना है और जल्द ही उड़ानें शुरू की जाएंगी, जिससे वंचित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा।
- Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN) was launched as a Regional Connectivity Scheme (RCS) under the Ministry of Civil Aviation in 2016. उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) को 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) के रूप में लॉन्च किया गया था।

CURRENT AFFAIRS

RCS-UDAN : New Airports आरसीएस–उड़ानः नए हवाई अड्डे

- The scheme connects remote areas, promoting tourism and economic growth, and has facilitated over 144 lakh passenger travels in its seven years. यह योजना दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ती है, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, और अपने सात वर्षों में 144 लाख से अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान की है।
- It supports last-mile connectivity and addresses unserved air routes. यह अंतिम–मील कनेक्टिविटी का समर्थन करता है और असेवित हवाई मार्गों को संबोधित करता है।
- The first RCS-UDAN flight was inaugurated by the Prime Minister in 2017, connecting Shimla to Delhi. शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली त्ब्–न्क।छ उड़ान का उद्घाटन 2017 में प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।

RCS-UDAN : New Airports आरसीएस–उड़ान: नए हवाई अड्डे

Versions of UDAN: उड़ान के संस्करण:

- UDAN 1.0: Awarded 128 flight routes to connect 70 airports (36 newly operational).
  UDAN 1.0: 70 हवाई अड्डों (36 नए परिचालन) को जोड़ने के लिए 128 उड़ान मार्गों को सौंपा गया।
- UDAN 2.0: Inclusion of helipads for the first time.
  उड़ान 2.0: पहली बार हेलीपैड का समावेश।
- UDAN 3.0: Introduce seaplanes for water aerodromes, enhancing connectivity in the North-East Region.
  UDAN 3.0: उत्तर–पूर्व क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए, जल हवाई अड्डों के लिए समुद्री विमान की शुरुआत।

RCS-UDAN : New Airports आरसीएस–उड़ानः नए हवाई अड्डे

- UDAN 4.0: Focused on North-Eastern regions, hilly states, and islands, facilitating operations for helicopters and seaplanes.
  उड़ान 4.0: उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे हेलीकॉप्टरों और समुद्री विमानों के संचालन में सुविधा होगी।
- UDAN 5.0: Prioritises Category-2 and Category-3 aircraft.
  उड़ान 5.0: श्रेणी–2 और श्रेणी–3 के विमानों को प्राथमिकता।
- UDAN 5.1: Boosts helicopter routes by increasing funding, lowering airfare caps, and requiring one destination to be a priority area.
  उड़ान 5.1: फंडिंग बढ़ाकर, हवाई किराया सीमा कम करके और एक गंतव्य को प्राथमिकता क्षेत्र बनाकर हेलीकॉप्टर मार्गों को बढ़ावा देता है।

RCS-UDAN : New Airports आरसीएस–उड़ानः नए हवाई अड्डे

- UDAN 5.2 : Enhances last-mile connectivity with small aircraft, boosting tourism in remote areas.
  न्क।छ 5.2ः छोटे विमानों के साथ अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देता है।
- UDAN 5.3 and 5.4 : To operationalize previously discontinued routes, further enhancing point-to-point air connectivity.
  उड़ान 5.3 और 5.4ः पहले बंद किए गए मार्गों को चालू करना, पॉइंट–टू–पॉइंट हवाई कनेक्टिविटी को और बढ़ाना।

UPM-YASASVI Scheme: यूपीएम–यासस्वी योजनाः

- The Ministry of Social Justice and Empowerment has implemented the PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM-YASASVI). सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट इंडिया (PM&YASASVI) के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना लागू की है।
- PM-YASASVI Scheme is a comprehensive umbrella scheme aimed at uplifting students from Other Backward Classes (OBC), Economically Backward Classes (EBC), and Denotified Tribes (DNT) by providing them with access to quality education during their formative years.
  पीएम–यासस्वी योजना एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजाति (डीएनटी) के छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके उनका उत्थान करना है।

UPM-YASASVI Scheme: यूपीएम–यासस्वी योजनाः

- It has consolidated and enhanced several earlier initiatives, including the Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship Scheme for EBCs and the Ambedkar Pre-Matric and Post-Matric Scholarship Scheme for DNTs, which were subsumed under this program starting from 2021-22. इसने पहले की कई पहलों को समेकित और बढ़ाया है, जिसमें ईबीसी के लिए डॉ. अंबेडकर पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और डीएनटी के लिए अंबेडकर प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शामिल है, जिन्हें 2021–22 से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था।
- By integrating these schemes, PM YASASVI aims to ensure a more streamlined and impactful approach to supporting the educational needs of socially and economically disadvantaged students.
  इन योजनाओं को एकीकृत करके, पीएम यशस्वी का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावशाली दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

UPM-YASASVI Scheme: यूपीएम–यासस्वी योजनाः

- The overarching goal of the scheme is to promote educational empowerment among these vulnerable groups, helping them overcome financial barriers and complete their education.
  योजना का व्यापक लक्ष्य इन कमजोर समूहों के बीच शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे उन्हें वित्तीय बाधाओं को दूर करने और अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी।
- Under this Scheme students can avail Pre-Matric Scholarship from Class 9 to 10 and Post Matric Scholarship for their higher studies at post-matriculation or post-secondary stage.
  इस योजना के तहत छात्र कक्षा 9 से 10 तक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट–मैट्रिक या पोस्ट–माध्यमिक स्तर पर अपने उच्च अध्ययन के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं।

UPM-YASASVI Scheme: यूपीएम–यासस्वी योजनाः

Eligibility: पात्रताः

- The Pre-Matric Scholarship is designed for students in classes IX and X attending government schools, प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा नौवीं और दसवीं के छात्रों के लिए डिजाइन की गई है।
- Family income below Rs. 2.5 lakh. पारिवारिक आय रु. 2.5 लाख.
- Implementing Agency : Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment. कार्यान्वयन एजेंसीः सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

National Mission for Manuscripts: पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशनः

- The Union Ministry of Culture is set to “revive and relaunch” the National Mission for Manuscripts (NMM) and is mulling the formation of an autonomous body to help preserve ancient texts in India.
  केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (एनएमएम) को ‘‘पुनर्जीवित और पुनः लॉन्च’’ करने के लिए तैयार है और भारत में प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित करने में मदद के लिए एक स्वायत्त निकाय के गठन पर विचार कर रहा है।
- Presently, NMM is a part of the Indira Gandhi National Centre for Arts.
  वर्तमान में, एनएमएम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक हिस्सा है।

National Mission for Manuscripts: पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशनः

- The new body, likely to be named the National Manuscripts Authority, will be an autonomous entity under the Ministry of Tourism and Culture.
  नई संस्था, जिसका नाम राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण होने की संभावना है, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त इकाई होगी।
- National Mission for Manuscripts (NMM) was established in February 2003, by the Ministry of Tourism and Culture, Government of India.
  भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (एनएमएम) की स्थापना की गई थी।
- Mandate: Documenting, conserving and disseminating the knowledge preserved in the manuscripts.
  अधिदेशः पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रसार करना।

National Mission for Manuscripts: पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशनः

- Motto: 'Conserving the past for the future'
  आदर्श वाक्यः 'भविष्य के लिए अतीत का संरक्षण'
- A unique project in its programme and mandate, the NMM seeks to unearth and preserve the vast manuscript wealth of India.
  अपने कार्यक्रम और अधिदेश में एक अनूठी परियोजना, एनएमएम भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा का पता लगाने और संरक्षित करने का प्रयास करती है।
- India possesses an estimate of ten million manuscripts, probably the largest collection in the world.
  भारत में अनुमानतः दस मिलियन पांडुलिपियाँ हैं, जो संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है।

National Mission for Manuscripts: पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशनः

- These cover a variety of themes, textures, and aesthetics, scripts, languages, calligraphies, illuminations, and illustrations.
  इनमें विभिन्न प्रकार के विषय, बनावट और सौंदर्यशास्त्र, लिपियाँ, भाषाएँ, सुलेख, रोशनी और चित्र शामिल हैं।
- While 75% of the existing manuscripts are in Sanskrit,25% are in regional languages, according to the NMM. एनएमएम के अनुसार, मौजूदा पांडुलिपियों में से 75: संस्कृत में हैं, जबकि 25: क्षेत्रीय भाषाओं में हैं

National Mission for Manuscripts: पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन:

Objectives: उद्देश्य:

- Locate manuscripts through a national-level survey and post-survey.
  राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण और सर्वेक्षण के बाद पांडुलिपियों का पता लगाएं।
- Document each and every manuscript and manuscript repository, for a National Electronic Database that currently contains information on four million manuscripts making this the largest database on Indian manuscripts in the world.
  राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के लिए प्रत्येक पांडुलिपि और पांडुलिपि भंडार का दस्तावेजीकरण करें, जिसमें वर्तमान में चार मिलियन पांडुलिपियों की जानकारी शामिल है, जो इसे दुनिया में भारतीय पांडुलिपियों पर सबसे बड़ा डेटाबेस बनाता है।

National Mission for Manuscripts: पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन:

- Conserve manuscripts incorporating both modern and indigenous methods of conservation and training a new generation of manuscript conservators.
  संरक्षण के आधुनिक और स्वदेशी दोनों तरीकों को शामिल करते हुए पांडुलिपियों का संरक्षण करें और पांडुलिपि संरक्षकों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें।
- To train the next generation of scholars in various aspects of Manuscript Studies like languages, scripts and critical editing and cataloguing of texts and conservation of manuscripts.
  अगली पीढ़ी के विद्वानों को पांडुलिपि अध्ययन के विभिन्न पहलुओं जैसे भाषाओं, लिपियों और महत्वपूर्ण संपादन और ग्रंथों की सूचीकरण और पांडुलिपियों के संरक्षण में प्रशिक्षित करना।

National Mission for Manuscripts: पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशनः

- To promote access to manuscripts by digitizing the rarest and most endangered manuscripts.
  दुर्लभतम और सबसे लुप्तप्राय पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करके पांडुलिपियों तक पहुंच को बढ़ावा देना।
- To promote access to manuscripts through the publication of critical editions of unpublished manuscripts and catalogues.
  अप्रकाशित पांडुलिपियों और कैटलॉग के महत्वपूर्ण संस्करणों के प्रकाशन के माध्यम से पांडुलिपियों तक पहुंच को बढ़ावा देना।
- To facilitate public's engagement with manuscripts through lectures, seminars, publications and other outreach programmes
  व्याख्यान, सेमिनार, प्रकाशन और अन्य आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से पांडुलिपियों के साथ जनता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना

National Mission for Manuscripts: पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन:

- To achieve this mandate, the mission has established more than 100 Manuscripts Resource Centres and Manuscripts Conservation Centres all over India. इस जनादेश को प्राप्त करने के लिए, मिशन ने पूरे भारत में 100 से अधिक पांडुलिपि संसाधन केंद्र और पांडुलिपि संरक्षण केंद्र स्थापित किए हैं।

Manuscript: पांडुलिपि:

- A manuscript is a handwritten composition on paper, bark, cloth, metal, palm leaf, or any other material dating back at least seventy-five years that has significant scientific, historical, or aesthetic value. पांडुलिपि कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते, या किसी अन्य सामग्री पर कम से कम पचहत्तर साल पुरानी एक हस्तलिखित रचना है जिसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य मूल्य है।

PM Modi and Spanish PM Pedro Sanchez Jointly Inaugurate Tata Aircraft Complex in Vadodara, Gujarat: पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया:

- Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Spain, Mr. Pedro Sanchez, jointly inaugurated the Tata Aircraft Complex for manufacturing C-295 military transport aircraft at the Tata Advanced Systems Limited (TASL) campus in Vadodara, Gujarat. This project, a first-of-its-kind private sector Final Assembly Line (FAL) for military aircraft in India, marks a significant step forward in India's journey towards indigenous defense production under the "Make in India, Make for the World" mission.

  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधान मंत्री श्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) परिसर में सी–295 सैन्य परिवहन विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह परियोजना, भारत में सैन्य विमानों के लिए अपनी तरह की पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन (एफएएल) है, जो ''मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड'' मिशन के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Rajasthan government has launched the Rajasthan Investment Promotion Scheme: राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की है:

- To encourage private investment and boost economic growth, the Rajasthan government has launched the Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2024. This new flagship initiative is designed to provide enhanced financial incentives across a broader range of sectors. The introduction of RIPS comes just ahead of the 'Rising Rajasthan' Global Investment Summit 2024.

  निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस) 2024 शुरू की है। यह नई प्रमुख पहल व्यापक क्षेत्रों में उन्नत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। त्प्ै की शुरुआत 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से ठीक पहले हुई है।